



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 578]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 8, 2005/ज्येष्ठ 18, 1927

No. 578]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 8, 2005/JYAISTHA 18, 1927

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 8 जून, 2005

का.आ. 789(अ).—जबकि विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) (यहां इसके बाद अधिनियम के रूप में उल्लिखित) दिनांक 10 जून, 2003 को लागू हुआ;

जबकि अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा (2) यह व्यवस्था करती है कि राज्य आयोग ऐसे चरणों में और ऐसी शर्तों (क्रास सब्सिडी और अन्य प्रचालनात्मक बाधाओं सहित), जिसे उसके द्वारा नियत तारीख के एक वर्ष के भीतर निर्दिष्ट किया जाए, के अधीन मुक्त पहुंच (ओपेन एक्सेस) लागू करेगा और क्रमिक चरणों में मुक्त पहुंच की सीमा निर्दिष्ट करने और छीलिंग के लिए प्रभार निर्धारित करने में यह ऐसी क्रास सब्सिडी और अन्य प्रचालनात्मक बाधाओं सहित सभी संगत कारकों पर विधिवत ध्यान देगा;

और जबकि अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा (2) का पहला परन्तुक यह व्यवस्था करता है कि राज्य आयोग द्वारा यथानिर्धारित छीलिंग के लिए प्रभारों के अतिरिक्त अधिभार के भुगतान पर क्रास सब्सिडी हटाने से पूर्व ऐसी मुक्त पहुंच की अनुमति दी जा सकती है;

और जबकि अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा (2) का दूसरा परन्तुक यह व्यवस्था करता है कि ऐसे अधिभार का उपयोग वितरण लाइसेंसधारी के आपूर्ति क्षेत्र के भीतर क्रास सब्सिडी के वर्तमान स्तर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाएगा;

और जबकि उत्पादक कंपनियों को विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 43क की उप-धारा (1) के खंड (ग) के उपबंधों (अधिनियम द्वारा निरस्त) के अधीन सक्षम सरकारों की सहमति से

किसी अन्य व्यक्ति के साथ विद्युत की बिक्री के लिए संविदा करने की अनुमति दी गई थी और ऐसी कंपनियों द्वारा विद्युत की बिक्री उस निरस्त कानून के अधीन किसी अधिभार के भुगतान के अधीन नहीं थी ;

और जबकि वितरण लाइसेंसधारी को राज्य सरकारों द्वारा भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 की धारा 27 (अधिनियम द्वारा निरस्त) के अधीन आपूर्ति के क्षेत्र के बाहर किसी व्यक्ति को ऊर्जा की बिक्री करने के लिए प्राधिकृत किया गया था और ऐसे वितरण लाइसेंसधारी द्वारा ऊर्जा (विद्युत) की आपूर्ति उक्त निरस्त कानून के अधीन किसी अधिभार के भुगतान के अधीन नहीं थी ;

और जबकि सक्षम सरकार की सहमति अथवा राज्य सरकार के प्राधिकार, जैसा भी मामला हो के अधीन उक्त निरस्त कानूनों के अंतर्गत बिक्री अथवा आपूर्ति किए जा रहे विद्युत के मामले में क्रास सब्सिडी का तत्व नहीं था और इसलिए उसके लिए किसी अधिभार की आवश्यकता नहीं थी ;

और जबकि विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 (निरस्त कानून) की धारा 43क की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अधीन किसी उत्पादक कंपनी द्वारा विद्युत की बिक्री पर और भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (निरस्त कानून) की धारा 27 के अधीन लाइसेंसधारी द्वारा अपने आपूर्ति क्षेत्र के बाहर किसी व्यक्ति को आपूर्ति किए जा रहे विद्युत पर (अधिभार लगाने के संबंध में अधिनियम की धारा 42 के उपबंधों की प्रयोज्यता) संबंधित कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं ;

अब, इसलिए केन्द्र सरकार अधिनियम की धारा 183 द्वारा सौंपी गई अपनी शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम के उपबंधों के असंगत नहीं होने के कारण निरस्त कानूनों के अधीन बिक्री अथवा आपूर्ति किए जा रहे ऐसे विद्युत के संबंध में कठिनाइयों को हटाने के लिए प्रावधान करने हेतु एतद्वारा यह आदेश करती है, नामतः ——

### 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ :

- (1) इस आदेश को विद्युत (कठिनाइयां हटाना) द्वितीय आदेश, 2005 कहा जा सकता है।
- (2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

### 2. विद्युत की बिक्री अथवा आपूर्ति पर अधिभार के भुगतान से छूट :

अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा (2) के अंतर्गत विद्युत अधिनियम, 1948 (अधिनियम द्वारा अब निरस्त) की धारा 43क की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अधीन सक्षम सरकार की सहमति से उत्पादक कंपनियों द्वारा बिक्री किए जा रहे विद्युत और भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (अधिनियम द्वारा अब निरस्त) की धारा 27 के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार पर वितरण लाइसेंसधारी के द्वारा आपूर्ति किए जा रहे विद्युत पर ऐसी सहमति अथवा प्राधिकार की वर्तमान वैधता तक कोई अधिभार अदा करने की अपेक्षा नहीं होगी।

[फा.सं. 23/18/2004-आर एंड आर]

अजय शंकर, अपर सचिव

**MINISTRY OF POWER  
ORDER**

New Delhi, the 8th June, 2005

**S.O. 789(E).**—Whereas the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) (hereinafter referred to as the Act) came into force on the 10th June, 2003;

And whereas sub-section (2) of section 42 of the Act provides that the State Commission shall introduce open access in such phases and subject to such conditions, (including the cross subsidies, and other operational constraints) as may be specified within one year of the appointed date by it and in specifying the extent of open access in successive phases and in determining the charges for wheeling, it shall have due regard to all relevant factors including such cross subsidies, and other operational constraints;

And whereas the first proviso to sub-section (2) of section 42 of the Act provides that such open access may be allowed before the cross subsidies are eliminated on payment of a surcharge in addition to the charges for wheeling as may be determined by the State Commission ;

And whereas the second proviso to sub-section (2) of section 42 of the Act provides that such surcharge shall be utilized to meet the requirements of current level of cross subsidy within the area of supply of the distribution licensee;

And whereas generating companies were allowed to enter into a contract for sale of electricity with any other person with the consent of the competent governments under the provisions of clause (c) of sub-section (1) of section 43A of the Electricity (Supply) Act, 1948 (repealed by the Act), and sale of electricity by such companies was not subject to payment of any surcharge under that repealed law;

And whereas distribution licensees were authorized by the State Governments to supply energy to any person outside the area of supply under section 27 of the Indian Electricity Act, 1910 (repealed by the Act), and supply of energy (electricity) by such distribution licensee was not subject to payment of any surcharge under the said repealed law;

And whereas in case of electricity being sold or supplied under permissions from competent government or authorizations of the State Government, as the case may be, under the said repealed laws, there was no element of cross subsidy and, therefore, there was no requirement of any surcharge for the same;

And whereas difficulties have arisen regarding the applicability of the provisions of section 42 of the Act with regard to the levy of surcharge on the sale of electricity by a generating company under clause (c) of sub-section (1) of section 43A of the Electricity (Supply) Act 1948 (repealed law) and also on the electricity being supplied by licensees to any person outside the area of their supply under section 27 of the Indian Electricity Act, 1910 (repealed law);

Now, therefore, the Central Government in exercise of its power conferred by section 183 of the Act, hereby makes this order to make provisions in respect of such electricity being sold or supplied under the repealed laws, being not inconsistent with the provisions of the Act, to remove the difficulties, namely:-

1. Short title and commencement.-

- (1) This order may be called the Electricity [Removal of Difficulties] second Order, 2005.
- (2) It shall come into force on the date of publication in the official gazette.

2. Exemption from payment of surcharge on the sale or supply of electricity.-

No surcharge would be required to be paid, in terms of sub-section (2) of section 42 of the Act on the electricity being sold by the generating companies with consent of the competent government under clause (c) of sub-section (1) of section 43A of the Electricity Act, 1948 (now repealed by the Act), and on the electricity being supplied by the distribution licensee on the authorization by the State Government under section 27 of the Indian Electricity Act, 1910 (now repealed by the Act), till the current validity of such consent or authorizations.

[F. No. 23/18/2004-R & R]

AJAY SHANKAR, Addl. Secy.